सोचा है कि गैस जो हमारी बर्बाद हो रही है उसको बचाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है तो उसके लिए कोई विदेशी टेक्नोलोजी या कोई विदेशी कम्पनी इस मामले मे मदद करने के लिए तैयार है या नहीं ? इस विषय में क्या हमारे मंत्रालय ने कभी विचार किया है या कोई हमारा प्रयास इस ओर हुआ है ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त : जहां तक गैस के उपयोग का सवाल है मंत्रालय ने विचार भी किया है और मंत्रालय काम भी कर रहा है । लेकिन मैं फिर नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि जहां गैस का उपयोग 57 परसेंट हो रहा था तीन साल पहले, अब वह 72 परसेंट हो रहा है । यह उन्ही कोशिशों का नतीजा है इस में कोई नयी टेक्नोलोजी की बात नहीं है । यह जो गैस है वहां जलानी पड़ती हैं जो बहुत-बहुत दूर-दूर है । इसका तरीका यह है कि वहां पर छोटे-छोटे गैस पावर प्लांट लगाये जायें । जैसा आन्ध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कहा है । गुजरात को कहा है, राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं और जगह भी कर रहे हैं । जो गैस यूटीलाइज करनी है, या उपयोग करनी है उसकी पूरी टेक्नोलोजी जो है वह हमारे पास है । हम लोग यह भी कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल नयी टेक्नोलोजी है वह हम को प्राप्त हो जाये और इस बारे में हम प्रयत्नशील हैं । लेकिन यह समस्या बनी रहेगी इसलिए कि गैस मिल रही है । जब तक गैस मिलती रहेगी तेल निकालने के लिए तो उसके साथ निकलने वाली गैस को निकालना होगा ही और जब तक उसका उपयोग नहीं करते तो जलाना पड़ेगा ही । लेकिन जहां खाली गैस मिलती है उसको सुरक्षित तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक कि हमारे पास संगठनात्मक ढांचा न बन जाये ।

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, it is a very good news that we are discovering crude oil and natural gas in several States. It comes to my mind that when Dr. B. C. Roy was the Chief Minister of West Bengal, he claimed royalty for the coal-bearing areas which were tapped by the Central Government. Now I would like to know from the hon. Minister whether they are giving any royalty amount to the States concerned, whether any States have already claimed the same, and if so, what is the Government's reaction?

SHRI BRAHM DUTT: Sir, we are paying royalty on the crude oil produced. Three years back it was increased by 300 per cent. Now perhaps we are paying Rs. 192 per tonne but after three years we will review the whole thing. We are receiving representations from the State Governments. We will review in due course.

SHRI MURASOLI MARAN: How much are you paying to States like Assam?

SHRI BRAHM DUTT: Rs. 192 per tonne. I think I am correct.

MR. CHAIRMAN: Question No. 465. Absent.

*465. [The questioner (Shri J. P. Goyal) was absent. For answer, vide col 36-37 infra).

Cumulative Losses of SEBs

*466. SHRI KAILASH PATI MISHRA:
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:†

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the cumulative losses incurred by each of the State Electricity Board during the last three years, year-wise and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ata Bihari Vajpayee.

(b) by when all the State Electricity Boards are likely to come out of the red and cease to be a burden on public exchequer?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) The position is given in the Statement laid on the Table of the House. [see below].

(b) The Electricity (Supply) Act, 1948 provides for each State Electricity Board to carry on its operations and adjust its tariffs in such a way as to earn a surplus of not less than 3 per cent of its net fixed assets at the beginning of the year. As per the action plans of the State Electricity Boards, most of them are expected to achieve a 3 per cent surplus by 1989-90.

Statement

Cumulative Surplus/(Deficit) of State Electricity Boards

(Rs. in crores)

Sl. No.	S.E.Bs.	As On		
		31-3-85	31-3-86	31-3-87
1	Andhra Pradesh	76.3	90.7	128 6
2	Bihar	(129 2)	(250 3)	(295.0)
3	Gujarat	7.8	6.1	75.2
4	Haryana	(312.6)	(374. 1)	(444.3)
5	Himachal Pradesh	(93.1)	(101.4)	(112.7)
6	Karnataka	135.6	156.3	106.4
7	Kerala	7.6	12.4	20.0
8	Madhya Pradesh	(50.8)	(29.7)	97.1
9	Maharashtra	(62.4)	(88.7)	(24 2)
10	Orissa	(63.5)	(73.7)	(88.3)
11	Punjab	(96.1)	(102.5)	(122.3)
12	Rajasthan	(161.7)	(209.5)	(223.2)
13	Tamil Nadu	90 4	118 3	215.1
14	Uttar Pradesh	(603.9)	(756.2)	(646.5)
15	West Bengal	(187.3)	(259.3)	(277.6)
16	Assam	(178 8)	(271 4)	NA
17	Meghalaya	(26 1)	(28.5)	(29.0)

N.B.: 1. On the basis of Annual Accounts submitted by the Boards.

2. Includes Rural Electrification Subsidies as exhibited in the Boards' accounts.

3. These losses have been worked out after charging gross interest to revenue for the years 1984-85 and 1985-86 and after capitalisation of Interest During Construction (IDC) for the year 1986-87.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, जो विवरण सभापटल पर रखा गया है उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है बल्कि उलझ गयी है । विवरण के अनुसार पिछले तीन सालों में महाराष्ट्र को छोड़ कर सभी राज्यों के बिजली बोर्ड घाटा कर रहे हैं और घाटा बढ़ता ही जा रहा है । उत्तर प्रदेश में 87 के आंकड़ों के हिसाब से 646 करोड़ का घाटा है । लेकिन मंत्री महोदया ने अपने विवरण में यह आशा भी प्रकट की है कि 1989–90 तक सभी बिजली बोर्ड तीन परसेंट का अधिशेष प्राप्त कर लेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि इस आशावाद का आधार क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, वाजपेयी जी को कुछ निराशावाद है, यह क्या है मैं नहीं कहना चाहती, परन्तु आज स्थिति उलझी नहीं है, काफी सुलझी है । मान्यवर, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगी कि पिछले वर्ष हमारे बहुत से राज्य बोर्डों ने अपना घाटा कुछ कम किया है और उनके कार्य में कुछ उन्नति भी हुई है । आज हमारे बहुत सारे बोर्ड हो सकते हैं जिन्होंने तीन प्रतिशत वाली स्टैच्युरी ओब्लीगेशन को भी पूरा करने का प्रयास किया है और बाकी राज्यों ने भी नक्शे के अंतर्गत अपना काम लाने का प्रयास किया है । इसलिए मुझे तो आशावाद ही दिख रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, बिजली बोर्ड के घाटे को कम करने के लिए एक तरीका यह है कि बिजली की दरें बढ़ाई जाएं, किसानों पर, उपभोक्ताओं पर और बोझा डाल दिया जाए । दूसरा, तरीका यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाए, गुणवत्ता बढ़ाई जाए, क्षमता बढ़ाई जाए, संचालन कुशलता बढ़ाई जाए । क्या केन्द्र ने इस बात का विवरण इकट्ठा किया है कि अगर चित्र आशावाद से भरा हुआ है तो क्या उसका कारण यह है कि बिजली बोर्ड अपना घाटा पूरा करने के लिए और अपनी अक्षमता पर पर्दा डालने के लिए बिजली की दरें अनाप-शनाप बढ़ाते जा रहे हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जितनी बातों का जिक्र अभी वाजपेयी जी ने किया है इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आशावादी हुए हैं । आज सब से पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पहले जो हमारा एकाउंटिंग प्रोसीजर था जिसमें कि एक सही तरीका कम्पेयरेबल इवेल्यूएशन करने का ही तरीका नहीं था उसको बाकायदा आज यूनिफार्म एकाउंटिंग प्रोसीजर बनाया गया है । सब का इवैल्यूएशन अच्छी तरह से हो रहा है और सब बिजली बोर्डों के माध्यम से यह भी कार्य चल रहा है कि जो इन्टरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो दिया जा रहा है उसको भी कैपिटलाइज़ कर लिया जाए और यह आदेश भी जारी हो गए और करीब-करीब 20 प्रतिशत इतना इन्टरेस्ट बढ़ जाता है और उनका कोई धन नहीं बचता जिसे और काम में लगा सकें । वाजपेयी जी को खुशी होगी कि यह चीज़ स्वीकृत हो गई है और इसका सारा आदेश जारी हो गया है और उसके अतिरिक्त भी सारे कदम उठाए गए हैं, चाहे मोनिटरिंग के हों, चाहे ट्रेनिंग के हों, चाहे खर्चे घटाने के हों, चाहे रेनोवेशन एंड माडर्नाइजेशन के हों सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी स्थिति उत्साहजनक है ।

श्री सभापति : हम सब लोग चाहते हैं कि आशावादी बनें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एकाउंटिंग प्रोसीजर की बात कही है, कहीं इसमें हेरा-फेरी तो नहीं हो रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कोई हेरा-फेरी नहीं हो रही है ।

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : सभापति जी, मैं एक बात और जानकारी के लिए जोड़ना चाहूंगा कि राज्य बिजली बोर्ड का काम आशाजनक है इसका एक प्रमाण यह है कि प्लांट लोड फैक्टर 52 से लेकर आज तक इस साल रिकार्ड 56.3 परसेंट जो कि अभी तक नहीं हुआ था इतना इतिहास में हुआ, यह एक बड़ी संतोषजनक स्थिति है । एक प्वाइंट प्लांटलोड फैक्टर बढ़ता है तो 500 मेगावाट के बराबर बिजली

की क्षमता बढ़ती है। इससे दिखेगा कि हमारा काम काफी आशादायक है और इससे वाजपेयी जी को संतोष होगा ।

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली बोर्डों का गठन कब से हुआ है, दूसरा यह कि जो खर्चा है सर्विसेज पर कितना है, तीसरा यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई बिजली बोर्ड है जो कि मुनाफे में चल रहा हो ? अगर नहीं तो घाटे का कुछ क्रम बतायेंगे कि किस राज्य में सब से ज्यादा घाटा है ?

श्री सभापति : यह तो दिया हुआ है इसमें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, यह तो दिया हुआ है ।

श्री राम चन्द्र विकल : किन्हीं दो राज्यों का बता दो ?

श्री सभापति : यह सब इसमें रहता है, वह भरा रहता है। सवाल करने से पहले जो विवरण रखा हो उसको जरूर देख लेना चाहिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, अगर आप अनुमति दें तो मैं इतना कहूं जैसे कि मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर यह मुनाफा न होता, अगर यह कार्यक्षमता न बढ़ती, अगर यह काम अच्छा नहीं होता तो एवरेज हमारे जो राज्य है उनका औसत जो 56 प्रतिशत नहीं है बल्कि अभी 50 प्रतिशत ही बची थी और आज 53.2 प्रतिशत है तो यह सराहनीय कार्य उन राज्यों के बिजली बोर्डों द्वारा हुआ है तो दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, तभी तो 50 से 53.2 प्रतिशत हुआ है ।

श्री घन श्याम सिंह : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक दो बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। उनके आशावाद के लिए तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वे थोड़ा सा काम में ज्यादा सुधार करें और तेज गति से सुधार करें तो अच्छा रहेगा। जहां तक घाटे की स्थिति का सवाल है, जैसा विकल जी ने पूछा है, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा घाटा हमारे बिजली बोर्ड को ही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि घाटे के मुख्य कारण क्या हैं ? क्या घाटे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके बिजली बोर्डस में जरूरत से ज्यादा स्टाफ है और बिजली बोर्डस में उतना काम नहीं होता है जितना होना चाहिए ? क्या दूसरा सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में यह है कि बिजली की जो चोरी होती है वह सबसे ज्यादा सफेदपोश समझे जाने वाले लोग करते हैं और उस कारण से घाटा होता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन सफेदपोश लोगों द्वारा की जा रही चोरी को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय सदस्य ने चोरी की बात कही है। हमारे घाटे में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन लौसेज भी है जिसमें चोरी का अंश भी है। यह कहना तो सही नहीं है कि कितना प्रतिशत है, लेकिन उस घाटे में चोरी का भी अंश है। पार्लियामेंट ने इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट में संशोधन किया है। इससे थोड़ा-सा लाभ हुआ है। मैं माननीय सदस्य की नोटिस में यह बात भी लाना चाहती हूं कि टैरिफ के कारण भी थोड़ा घाटा उठाना पड़ता है। अभी हम जो बिजली का उत्पादन करते हैं उसमें औसत 80 या 82 पैसे प्रति यूनिट हमें पड़ता है। हम किसान भाइयों को कृषि को बढ़ाने के लिए बिजली देते हैं। उनको हम औसत कोई 17 या 18 पैसे प्रति यूनिट देते हैं। इससे कोई 62 पैसे का घाटा हमें सीधे उठाना पड़ता है। इसके साथ-साथ सूखे की स्थिति होने के कारण किसानों को कृषि के लिए ज्यादा बिजली दी गई है। इसकी जितनी संख्या बढ़ जाती है उतना ही घाटा एक साल में करीब-करीब बढ़ जाता है। हमारे अनुमान से कोई 14-15 सौ करोड़ का घाटा तो केवल टैरिफ के कारण उठाना पड़ता है। इसको हमें समझना है और साथ-साथ चोरी को भी रोकना है।

श्री घन श्याम सिंह : सफेद पोश लोगों द्वारा जो चोरी होती है उनको पकड़ने के लिए आप क्या कर रहे है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, माननीय सदस्य अगर ऐसे लोगो के नाम, सफेदपोश लोगों के नाम, हमारे पास भेजे देंगे तो चाहे वे सफेदपोश हो या कालेपोश हो, हम अवश्य जांच करके देख लेंगे ।

SHRI DEBA PRASAD RAY: I would like to know from the hon. Minister as to what is the quantum of losses incurred by the State Electricity Board of West Bengal in the last three years and how far this phenomenon is linked with under-utilisation of power plants in the State of West Bengal.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: The West Bengal State Electricity Board is not doing very well. I must say, as a matter of fact, we had great expectations, but for some reason or other, whether it is lack of discipline or supply of its equipment not reaching in time, it did not come up to our expectations. West Bengal State Electricity Board is one of the boards which should have and could have definitely done better.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Then hon. Minister has stated that the plant load factor in many State Electricity Boards has increased and it is a welcome feature. But I would like to draw attention to one imporant factor with regard to the plant load factor and that it bad supply of coal. Will the hon. Minister tell the House what steps he has taken to get the correct type of coal from the collieries supplied to the electricity boards and thermal plants? If good coal is supplied in the Electricity Boards, to my mind 2 to 3 per cent increase in the plant load factor is easily to be achieved. So, I would like to know what steps he has taken and how he is ensuring good coal supply to the electricity boards and the thermal plants.

SHRI VASANT SATHE: Actually, it is on account of supply of good quality coal. And when we say good quality coal, in our country the main problem is of high ash content of coal. High ash content of coal you can neither, as I have repeatedly said, wish away nor wash away. Because ash is in the structure of the coal in our country.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Give wishy or washy reply.

SHRI VASANT SATHE: Neither wishy nor washy.

Therefore, Sir, formerly we use to have the problem of extraneous matter getting with the coal. We have now ensured that extraneous matter like stones, shale, etc., does not go by introducing deshaling plant, coal handling plant and all the system. It is, in fact, because of close monitoring of the supply of coal that we have been able to achieve these good results of improving plant load factor. That is one of the factors. We are assuring our power-users that proper quality of coal will be supplied to them.

श्री सत्य पाल मलिक : श्रीमन्, माननीय राज्य मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है उसके सिलसिले में मैं जानना चाहूंगा और मैं उनके इस वक्तव्य का खंडन करता हूं, इसको गलत समझता हूं कि सिर्फ किसानों को सब्सीडी देने के कारण बिजली बोर्डों को घाटा हो रहा है । अगर यह मान लिया गया तो यह बडी खतरनाक बात होगी । श्रीमन्, बिजली बोर्डो के घाटे के एक हजार एक कारण हैं और केवल यह नही है । एक तो आप बिजली पैदा कम करते हैं, 40 सैकड़ा, 42 प्रतिशत आपका प्लान्ट लोड फैक्टर है और 22 प्रतिशत आपका रास्ते में चोरी होती है । जिसको आप चोरी बोलते हैं वह कायदे में ट्रांसमिशन लास कहा जाता है । इसकी सिनेमा घरों के मालिक, कोल्ड स्टोरेज के मालिक और सेठ लोग चोरी करते हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : बड़े उद्योग वाले।

श्री सत्य पाल मलिक : बडे उद्योग वाले करते हैं। इसके अलावा स्वयं जो आपके बिजली बोर्ड हैं उसके बारे में बहुत दिनों से बहस चल रही है कि उनको चलाने वाले टैक्नीकल लोग हों या आफिसर लोग हों। वहां पर आई०ए०एस० लोग बैठ जाते हैं। इसी तरह राज्य में बिजली मंत्रालय किसी स्टेट मिनिस्टर को दे दिया जाता है और 6 महीने के बाद उसको बदल दिया जाता है। अगर वहां पर किसी कम्पीटेन्ट मिनिस्टर को रखा जाय तो वह बिजली बोर्ड के आदमियों पर ठीक से अंकुश लगा सकता है लेकिन इसके अभाव में ऐसा नही हो पाता। इसी प्रकार इसके और बहुत से कारण हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अरण्य-रोदन कई सालों से चल रहा है और इस बीच एक खतरनाक बात यह हो गई है कि हम ताप बिजली घरों के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गये हैं और यह एक ऐसा विसियस सर्किल है कि कोयला नही है, कोयले की हड़ताल है, उसके लिये वैगन नहीं मिलते हैं, रेल वाले कहते हैं कि वैगन इसलिये नहीं क्योंकि बिजली और डीजल नहीं है और पूरी तरह से यह एक दुश्चक्र चला हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बिजली की मांग और पूर्ति में जो फर्क है, जो देश की जरूरत है और देश में उसका जितना उत्पादन होता है इन दोनों में जो फर्क है इसके मिटाने के लिये हाइडल से जो बिजली पैदा करने के सोर्सेज हैं उन को टैप करने के लिये, उनका इस्तेमाल करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, पहले जो माननीय सदस्य ने शंका प्रकट की है उसका मैं निराकरण करना चाहूंगी। यह केवल किसानों को जिस दर पर बिजली दी जा रही है उसके कारण ही यह सारा घाटा नहीं है। पर यह भी इसका एक मुख्य मुद्दा है। साथ ही साथ जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंटस को एग्रीकल्चर के लिये सब्सीडी देनी चाहिए और जो मांडेटरी है, वर्ल्ड बैंक के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार वह समय समय पर नहीं दे रहे हैं। अगर कम से कम यह रुपया भी हमारी स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया जाय तो उन्हें अपना काम सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग मिल सकता है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि कोयले के ऊपर निर्भर होने के बजाय पन बिजली के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो मैं कहना चाहूंगी कि सरकार इस चीज को बड़े ध्यान से देख रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम पानी से बिजली उत्पन्न कर सकें। मान्यवर, आज हमारे देश में जितना पोटेंशियल है उससे 84 हजार मेगावाट बिजली हम केवल पानी से उत्पन्न कर सकते है लेकिन आज हम केवल 12 प्रतिशत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पंचवर्षीय योजना के बाद वह बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाय यह हमारा प्रयास है। पानी से बिजली पैदा करने के लिये आपने देखा है कि बड़ी योजना टिहरी में आगे बढ़ रही है जो कि 24 सौ मेगावाट की है और छोटी छोटी भी बन रही है। हमें आशा है कि यह कार्य भविष्य में और आगे बढ़ता चला जायेगा।

*467. [*The questioner (Shri Ajit P.K. Jogi) was absent. For answer, vide col.* 37-38 infra.]

*468. [*The questioner (Shri Satya Prakash Malaviya) was absent. For answer,* vide *col.* 38—43 infra.]

*469. [*The questioners (Shri Lal K. Advani and Shri Ashwani Kumar) were absent. For answer,* vide *col.* 43—45 infra.]

Uniform Power Tariff for Agricultural Sector

*470. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:†
SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Central Government has recently issued any direc-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Harvendra Singh Hanspal.